**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2996**

**दिनांक 21 मार्च, 2018**

**ओ॰एन॰जी॰सी॰ के प्रमुख क्षेत्रों का निजीकरण**

**2996. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 11 प्रमुख क्षेत्रों का निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कदम से यह अग्रणी अन्वेषक कम्पनी जिसके पास भारत के विकसित ब्लॉक हैं जिनका उत्पादन समाप्त होने वाला है, अपनी बहुमूल्य महत्वपूर्ण आस्तियों से वंचित हो जाएगी;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप नई संभावनाओं का सृजन होगा जिसमें विकास के लिए अत्‍यधिक निवेश की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) से (घ) :**अलग-थलग अवस्थिति, लघु आकार, अत्‍यधिक विकास लागत और प्रौद्योगिकीय अड़चनों जैसे अनेक कारणों से कई वर्षों से ओएनजीसी और ओआईएल के खोजे गए तेल और गैस क्षेत्रों में से अनेक क्षेत्रों से मुद्रा अर्जित नहीं की जा सकी है। सरकार ने घरेलू उत्‍पादन बढ़ाने के उद्देश्‍य से राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा की गई खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए अनेक नीतियां लागू की हैं। सरकार ने पूर्व में वर्ष 1992-93 में एनईएलपी पूर्व खोजे गए क्षेत्रों के दौर में निजी भागीदारी की अनुमति दी थी। तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्‍य से सरकार ने सितंबर, 2015 में ओएनजीसी और ओआईएल के खोजे गए ऐसे 69 लघु क्षेत्रों, जिनसे उत्‍पादन शुरू नहीं किया गया था, से मुद्रा अर्जित करने के लिए खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति को अनुमोदित किया। हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय (डीजीएच)/सरकार ओएनजीसी तथा ओआईएल सहित विभिन्‍न पणधारकों के साथ परामर्श करके तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्‍न विकल्‍पों का अध्‍ययन कर रही है और उनका मूल्‍यांकन कर रही है। इन विकल्‍पों में खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी बोली का अन्‍य दौर, तकनीकी सेवा संविदा मॉडल और फार्मिंग-इन मॉडल शामिल हैं।

\*\*\*\*